



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 22]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 24, 2001/माघ 4, 1922

No. 22]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 24, 2001/MAGHA 4, 1922

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2001

संख्या एम-13011/3/99-प्रशा. IV.— भारत सरकार ने डा० सी. रंगाराजन, राज्यपाल, आन्ध्र प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 19.01.2000 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग का गठन किया। आयोग में डा० सी. रंगाराजन इसके अंशकालिक अध्यक्ष तथा निम्नलिखित अधिकारी अंशकालिक सदस्यों के रूप में हैं

- (1) श्री वी.आर. राव, भूतपूर्व निदेशक, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन और संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार।
- (2) श्री एस.एन. विघ्वांस, भूतपूर्व निदेशक (अर्थ एवं सांख्यिकी) महाराष्ट्र सरकार और संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ।
- (3) प्रो. जे. राय, अवकाश प्राप्त प्रोफेसर, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान।
- (4) डा. प्रेम नारायण, अवकाश प्राप्त वैज्ञानिक, आई.ए.आर.आई. और भूतपूर्व निदेशक, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान।
- (5) डा. राकेश मोहन, महानिदेशक, एनसीईआर।
- (6) डा. वी.आर. पंचमुखी, महानिदेशक, गुटनिरपेक्ष और अन्य विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली।
- (7) डा. वाई. वेणुगोपाल रेड्डी, उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक।
- (8) डा. के. श्रीनिवासन, कार्यकारी निदेशक, भारत का जनसंख्या प्रतिष्ठान और भूतपूर्व निदेशक, जनसंख्या अध्ययन का अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान।
- (9) प्रो. एस. तेन्दुलकर, दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स और उपाध्यक्ष सांख्यिकी संबंधी राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड।
- (10) डा. ए.बी.एल. श्रीवास्तव, मुख्य परामर्शदाता, शैक्षिक परामर्शदाता भारत लि. और भूतपूर्व प्रोफेसर, एनसीईआरटी।
- (11) डा. फेडी आरडेशिर मेहता, प्रख्यात निजी सेवा अर्थशास्त्री और निदेशक, मैसर्स टाटा सन्स लि.।

2. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की सेवा-शर्तें इस प्रकार हैं :
- 1) मौजूदा सांख्यिकी प्रणाली की कमियों की समयबद्धता, विश्वसनीयता और पर्याप्तता के संदर्भ में आलोचनात्मक जांच करना ।
  - 2) प्रशासनिक ढांचे के भिन्न-भिन्न स्तरों पर सरकार में नीति और आयोजना के प्रयोजनार्थ समयबद्ध और विश्वसनीय सांख्यिकी के सृजन हेतु सांख्यिकीय प्रणाली की कमियों को दूर करके इसे सुदृढ़ करने के उपायों की अनुशंसा करना ।
  - 3) देश में विकेन्द्रीयकृत सांख्यिकीय प्रणाली के समेकित विकास को सुनिश्चित करने हेतु स्थाई और कारगर समन्वयक मकैनिज्म की अनुशंसा करना ।
  - 4) सांख्यिकीय सूचना के संग्रहण के लिए मौजूदा विधायन की समीक्षा करना और समयबद्ध, विश्वसनीय और पर्याप्त सांख्यिकी के संग्रहण और प्रसार के प्रयोजन को प्राप्त करने हेतु, जहां आवश्यक हो, संशोधन की अनुशंसा करना ।
  - 5) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (सांख्यिकी पक्ष) और भारत की अन्य सांख्यिकीय इकाईयों, मौजूदा संगठन की समीक्षा करना और सांख्यिकी सेवाओं की वृद्धि और विकास से निपटने हेतु कर्मचारीवृन्द और प्रशिक्षण अपेक्षाओं की अनुशंसा करना ।
  - 6) भारत सरकार और स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की रेंज की सांख्यिकीय लेखा-परीक्षा शुरू करने की आवश्यकता की जांच करना और इसके बारे में उपयुक्त अनुशंसा करना, और
  - 7) देश में सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार करने के लिए अन्य उपायों की अनुशंसा करना ।

3. आयोग की सहायता अपर सचिव के स्तर पर पूर्णकालिक सचिव की अध्यक्षता में सचिवालय द्वारा की जाती है ।

4. आयोग का गठन अधिसूचना की तारीख से 12 महीनों की अवधि के लिए किया गया था । मंत्रिमण्डल के अनुमोदन से अपर सचिव के स्तर पर सचिव, राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के पद सहित इसके सचिवालय के लिए मंजूर तथा धारित सभी पदों सहित राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की अवधि 19 जनवरी, 2001 से 18 जुलाई, 2001 तक छः महीनों की अवधि के लिए और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है ।

एन. एस. शास्त्री, महानिदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन

#### MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

#### RESOLUTION

New Delhi, the 23rd January, 2001

No. M-13011/3/99/Adm. IV.— The Government of India established a National Statistical Commission under the chairmanship of Dr. C. Rangarajan, Governor, Andhra Pradesh vide Gazette Notification dated 19<sup>th</sup> January, 2000. The Commission consists of part-time chairman Dr. C. Rangarajan, Governor, Andhra Pradesh and 11 part-time members:

- (1) Shri V. R. Rao, ex-Director, Central Statistical Organisation and UN Advisor
- (2) Shri S. M. Vidwans, ex-Director (Economics & Statistics), Government of Maharashtra and UN expert
- (3) Prof. J. Roy, Professor Emeritus at Indian Statistical Institute
- (4) Dr. Prem Narain, Emeritus Scientist, IARI and ex-Director, Indian Agricultural Statistics Research Institute
- (5) Dr. Rakesh Mohan, Director-General, NCAER
- (6) Dr. V. R. Panchmukhi, Director-General, Research and Information System for the Non-Aligned and other Developing Countries
- (7) Dr. Y. Venugopal Reddy, Deputy Governor, Reserve Bank of India
- (8) Dr. K. Srinivasan, Executive Director, Population Foundation of India and ex-Director of International Institute of Population Studies
- (9) Prof. S. Tendulkar, Delhi School of Economics and Vice-Chairman, National Advisory Board on Statistics
- (10) Dr. A. B. L. Srivastava, Chief Consultant, Educational Consultants India Ltd., & ex-Professor, NCERT
- (11) Dr. Fredie Ardeshir Mehta, Eminent private sector economist and Director, M/s Tata Sons Ltd.

2. The terms of reference of the National Statistical Commission are as follows:

- (i) To examine critically the deficiencies of the present statistical system in terms of timeliness, reliability and adequacy.
- (ii) To recommend measures to correct the deficiencies and revamp the statistical system to generate timely and reliable statistics for the purpose of policy and planning in Government at different levels of administrative structure.
- (iii) To recommend permanent and effective coordinating mechanism for ensuring integrated development of the decentralised statistical system in the country;
- (iv) To review the existing legislation for the collection of statistical information and to recommend amendments, where necessary, to achieve the objective of collection and dissemination of timely, reliable and adequate statistics;
- (v) To review the existing organisation of the Ministry of Statistics & Programme Implementation (Statistics Wing) and other statistical units of the Government and to make recommendations on their staffing and training requirements to enable them to cope with the increase and development of statistical services;

- (vi) To examine the need for instituting statistical audit of the range of services provided by the Government and local bodies and make suitable recommendations thereof; and
- (vii) To recommend any other measures for improving the statistical system in the country.

3. The Commission is assisted by a Secretariat headed by a full time Secretary at the level of Additional Secretary.

4. The Commission was set up for a term of 12 months from the date of notification.

With the approval of the Cabinet it has, now, been decided to further extend the tenure of the National Statistical Commission for a period of six months from 19<sup>th</sup> January, 2001 to 18<sup>th</sup> July, 2001 along with all the posts sanctioned and occupied for its secretariat including the post of Secretary, National Statistical Commission at the level of Additional Secretary.

N. S. SASTRY, Director General and Chief Executive Officer  
National Sample Survey Organisation